

makes an invidious distinction between workers, and at the same time by categorising them, they suffer a financial loss. I have seen the order of the Finance Ministry, and they have said: "...in the interests of the Corporation and its policyholders a reduction in the remuneration payable and a revision of the other terms and conditions applicable to the classes of employees aforesaid are called for;"

They are going to revise the pay-scales of these employees, and that is going to affect them; and there is the categorisation scheme that is going to inflict a huge financial loss on these people. At the same time, it might go to the extent of terminating their services. This is one thing.

Mr. Speaker: I am sure some people will be hit, some people will not be hit. So far as the particular financial loss is concerned, shall we go into this matter? It is likely to cause financial loss, therefore it is likely to create an explosive situation, it is likely to lead to a strike and so on and so forth. I have never hesitated to give opportunity to Members here to bring matters to the notice of the House and the Government for taking proper action in particular matters which are of great importance, but I do not think that an adjournment motion is the proper procedure.

So far as these employees, their scales of pay etc., are concerned, I think in the last session Shri Sadhan Gupta or somebody else made some reference to this, and we allotted some time—I am not clear in my mind—but if it is such a serious matter and of great importance, I will look into it. Hon. Members may try to have some time for discussion. I will consider that. So far as the adjournment motion.....

Shri Hem Barua: There is another point.

Mr. Speaker: I have heard sufficiently about it. This adjournment motion is not the proper method. I reject that motion—not that I am not going to allow discussion on it. In case it is

a matter of importance, later on I shall consider.

I have got so many adjournment motions. (*Laughter*).

Raja Mahendra Pratap (Mathura): I beg to say there should be no laughter when there is such a serious question as an adjournment motion.

Mr. Speaker: I agree with the hon. Member that there ought not to be laughter in all cases.

There are one or two other adjournment motions. I will consider them, and if I do not give my consent, I will inform the hon. Members, and if I feel that I want some elucidation from any hon. Member, I will bring it up before the House tomorrow.

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: I beg to lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 10th February, 1958.

President's Address

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, संसद् के नये सत्र का भार संभालने के समय आप का पुनः स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इस योजना के द्वितीय वर्ष के आरम्भ से ही हमारी आर्थिक व्यवस्था पर काफ़ी दबाव रहा है। अपने गत मई के अभिभाषण में मैंने आप से कहा था :—

“जिन कमियों का मैं ने जिक्र किया है उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-सम्बन्धी काम को स्थगित कर दें, पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को मुलभूताने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिये अपने साधनों

[राष्ट्रपति]

को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या से और इसके लिये आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहाँ जैसी जरूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटा कर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाये और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जावे।"

आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मेरी सरकार ने ऐसे कड़े उपाय अपनाये हैं जो योजना-बद्ध रचनात्मक कार्यक्रम की कठिनाइयों को दूर कर सकें, जो मुद्रा-स्फीति-संबंधी प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर सकें, जो विदेशी मुद्रा विनिमय की स्थिति से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें और जो योजना के अन्तर्गत सभी कामों की पूरा करने में सहायक हो सकें। इस दिशा में मेरी सरकार ने अभी तक जो कदम उठाये हैं उनका फल अच्छा हुआ है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले महीनों में हमारी स्थिति में सुधार भी हुआ है। आयात कम करने के लिये और विदेशी मुद्रा का उपाजन करने के लिये सरकार ने जो कार्यवाही की है उसके कारण विदेशी पावने के ह्रास की गति कम हो गयी है। ऋण द्वारा और कुछ योजनाओं के संबंध में विशेष व्यवस्था द्वारा, आवश्यक पूंजीगत सामान के लिये स्थगित अदायगी की व्यवस्था से और अत्यन्त आवश्यक कामों को छोड़ कर सभी मदों के लिये विदेशी मुद्रा के प्रयोग पर रोक लगा कर, सरकार ने स्थिति में सुधार करने का यत्न किया है और बहुत हद तक यह इसमें सफल भी हुई है। इस संबंध में मैं उन देशों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन से हमें इस संबंध में सहा-

यता मिली है। मैं यहाँ सोवियत संघ, कनेडा, जर्मनी, जापान, और विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का धिक् करना चाहूंगा।

उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बचत हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। अधिक उत्पादन से विदेशी विनिमय की हमारी आवश्यकतायें कम रहेंगी और विनिमय के उपाजन में सहायता मिलेगी। बचत द्वारा मुद्रास्फीती की रोक थाम होगी और हमारे आन्तरिक साधनों को बल मिलेगा। इन दोनों कामों के लिये यह आवश्यक है कि जन साधारण इन समस्याओं को समझें और कुरबानी के लिये तैयार रहें, सतर्क रहें, मितव्ययिता को अपनाएं और जनमत द्वारा समर्थन करें।

विदेशी मुद्रा-संबंधी और वित्तीय मामलों के बारे में मेरी सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है उससे हमारी अर्थ-व्यवस्था के स्थाई रहने में मदद मिली है। १९५६ में और १९५७ के आरम्भ में चीजों के दाम ऊंचे चढ़ते जा रहे थे किन्तु इस कार्यवाही के फलस्वरूप कीमतों का बढ़ना रुक ही नहीं गया बल्कि गत वर्ष के अन्तिम महीनों में उनमें कुछ कमी भी हुई, जो अभी जारी है। हमारे देनदारी के खातों के घाटे में भी काफी कमी हुई है। पिछले साल की अपेक्षा साख-संबंधी स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हुआ है। हमारे बैंक-सम्बन्धी साधनों में वृद्धि हुई है और बैंकों द्वारा मंजूर किये गये ऋण भी अन्दाज के अन्दर रहे हैं। सट्टे की प्रवृत्ति को दबाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक स्थिति पर कड़ी दृष्टि रखेगा।

देश के भीतर मूल्यस्तर और विदेशों में अदायगी की हमारी क्षमता से सख्त अनाजों की उपलब्धि और उनकी कीमत का गहरा संबंध है। सूखा के कारण देश के कुछ भागों में फसलों की बरबादी हमारे लिये धार चिन्ता का विषय है। सरकार के पास अनाज का भंडार है और आयात द्वारा इस संचय को उचित स्तर पर स्थिर रखा जायेगा। इस के साथ ही अन्न के परिबहन पर सीमित किन्तु

अनिवार्य नियन्त्रण भी किया गया है। अनाज के व्यापार के लिये बैंकों द्वारा उधार दिये जाने का भी मेरी सरकार ने नियमन किया है ताकि अनुचित संग्रह न किया जा सके। सरकार ने सस्ते अनाज की दूकानों द्वारा बड़े पैमाने पर जनता में अन्न के वितरण की व्यवस्था भी की है। इन उपायों से महंगाई की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम हुई है।

फसलों के खराब हो जाने के बावजूद, १९५६-५७ में उत्पादन अधिकतम हुआ है जो १९५३-५४ में हुआ था। कुल खाद्य उत्पादन ६ करोड़, ८७ लाख टन हुआ जो १९५५-५६ की अपेक्षा ५ प्रतिशत अधिक था। कृषि उत्पादन की अखिल भारतीय देशना के अनुसार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यापारी फसलों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो कपास के उत्पादन में १८ प्रतिशत तथा गन्ने और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः १३ और ६ प्रतिशत रही है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये अपूर्व प्रयास किया जा रहा है। अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है।

औद्योगिक उत्पादन में भी काफी मुधार हुआ है। विदेशी विनिमय की कमी के कारण आयात में काटछांट का एक सुपरिणाम यह हुआ है कि इस से देश के साधनों तथा क्षमता का अधिक उपयोग और विकास का अवसर मिला। सरकारी और गैर-सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इस दिशा में प्रगति अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसी प्रकार हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को उन्नत कर सकते हैं, और इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति भी है। यद्यपि इस नीति की सफलता का आधार आवश्यकता है, फिर भी इस के कारण विदेशी साधनों पर हमारे उद्योग की निर्भरता कम हो सकेगी।

१९५७ में कोयले का उत्पादन ४ करोड़ ३० लाख टन हुआ, जो उत्पादन की नयी

सीमा थी, जबकि १९५६ में यह उत्पादन ३ करोड़ ६० लाख टन था। बहुत से नये क्षेत्रों में कोयले की खोज के लिये खुदाई और पूर्वोक्षण किये गये हैं और आशा की जाती है कि कुछ ही महीनों में बहुत सी नयी खानों में काम चालू किया जा सकेगा।

अभी हाल में आसाम श्रियल कम्पनी के साथ समझौता किया गया है जिस के अनुसार रूपया कम्पनी स्थापित की जायेगी और इस में ३३ १/३ प्रतिशत हिस्सा सरकार का होगा। इस कम्पनी का काम नाहरकटिया के कूपों में तेल का उत्पादन और वहाँ से तेल का परिवहन होगा। तेल की मफाई के लिये आसाम और बिहार में दो कारखाने स्थापित होंगे। तेल के लिये देश के दूगरे भागों में भी पूर्वोक्षण और ड्रूट खोज की जा रही है।

भारतीय जहाजों के अखिलम्ब निर्माण और विकास के लिये एक जहाज निर्माण कोष की स्थापना की गई है; इस कोष का आधार भारतीय मुद्रा होगा जिससे कि इस काम के लिये आर्थिक साधन निश्चित रूप में उपलब्ध हों। यह कोष स्थायी होगा और इसकी प्रति वर्ष मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।

बहुमुखी नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में संतोषजनक प्रगति हो रही है। दामोदर घाटी में माटथोन बांध का उद्घाटन गत सितम्बर में हुआ गया था। भाखरा योजना के संबंध में कार्यक्रम के अनुसार ही नहीं बल्कि उस से बढ़ कर प्रगति हो रही है। नागार्जुन मागर में निर्माण का काम गत जुलाई मास में आरम्भ किया गया। दूसरी बहुमुखी योजनाओं पर भी संतोषजनक रूप से कार्य जारी है।

भारी उद्योगों की दिशा में काफी प्रगति हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में एक भारी मशीन बनाने का कारखाना और कई एक अन्य योजनायें सोवियत संघ की सरकार

[राष्ट्रपति]

द्वारा दी गई विशेष ऋण की सहायता से चालू की जायेंगी। लोहा ढालने का एक बड़ा कारखाना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नंगल में वैज्ञानिक खाद्य का एक बड़ा कारखाना इंग्लैंड, फ्रांस और इटली की आर्थिक सहायता से बन रहा है। नेवेली में भी खाद्य का एक कारखाना बनाने की योजना है। बिजली का सामान तैयार करने के लिये एक बड़ा कारखाना ब्रिटिश सहायता से भोपाल में बनाया जायेगा। ऊरकेला, भिलार्ड और दुर्गापुर में इस्पात के बड़े कारखानों के निर्माण की दिशा में काफी प्रगति की जा चुकी है।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन १९५३ में किया गया था, अब काफी आगे बढ़ चुका है और इस के कारण मलेरिया की बहुत कुछ रोक-थाम हुई है। अब हमारा ध्येय इस बीमारी का पूर्ण उन्मूलन है। फाइलेरिया नियंत्रण के कार्य में भी अच्छी प्रगति हुई है। गंदी और पुरानी बस्तियों के सुधार का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्र में हम बराबर उन्नति कर रहे हैं। और हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास संबंधी समस्याओं के मुलमाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। टेक्निकल जनशक्ति के साधनों के विस्तार के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है।

पिछले वर्ष में आणविक शक्ति विभाग का काफी विस्तार किया गया। दो नये रियेक्टर और कई नये यन्त्र इस समय बनाये जा रहे हैं। मौजूदा वर्ष के समाप्त होने तक आणविक शक्ति के लिये और रियेक्टरों के लिये ईंधन के रूप में उपयुक्त युरेनियम धातु का उत्पादन शुरू हो जायेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में एक या अधिक आणविक शक्ति केन्द्र स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका करीब ढाई साल पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, पर्याप्त उन्नति की है। राज्यों की सरकारों के प्रबन्ध में मध्यम बैंक, जिन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के रूप में चलाया जायेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिक निकट लाये जा सके, इस के लिये कई सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

योजना आयोग केन्द्र और राज्यों के लिए वार्षिक योजनाएं बनाने में और उपलब्ध साधनों की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आवश्यक मंशोधन करने में व्यस्त है। इस के साथ ही आयोग को इस बात का ध्यान रखना है कि देश के विकास संबंधी कार्यक्रम को किसी प्रकार का धक्का न लगे। इस संबंध में योजना के मूल तत्वों के बारे में आयोग के प्रयत्नों के परिणाम मेरी सरकार इस सत्र में आपके सामने रखेगी।

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सामुदायिक विकास केन्द्रों की संख्या हम समय २,१५२ है जिन में २,७६,००० ग्राम आते हैं। इन ग्रामों की जनसंख्या १५ करोड़ है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया है कि प्रत्येक केन्द्र को ही आयोजन और विकास की इकाई और सब विकास भागों की सामान्य एजेंसी माना जाय। इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय विकास बजटों को केन्द्र के बजट से समन्वित किया जाय। विकास केन्द्र अधिकारी को इस बजट के संचालन का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रशासन के क्षेत्र में अधिक विकेन्द्रीयकरण का फैसला भी किया है और यह निश्चय किया है कि ग्रामों में और जिलों में सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये जायें। विकेन्द्रीयकरण की योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सरकारें ही स्वयं तैयार करेंगी। सुधरी हुई खेती को प्रोत्साहन

देने के उद्देश्य से कृषक नेताओं की ट्रेनिंग की एक योजना चामू की गई है।

राज भाषा आयोग की सिफारिशों इस समय विचाराधीन हैं। संसद् के ३० सदस्यों की एक समिति उनका अध्ययन कर रही है। संसद् के सदस्यगण, इस संबंध में कोई भी आदेश जारी किये जाने से पहले, आपको आयोग के प्रतिवेदन पर और संसद् की समिति के विचारों पर अपना मत प्रकट करने का अवसर अविलम्ब दिया जायेगा।

दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन अधिनियम, १९५७ के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में निगम स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

कपडा और चीनी उद्योगों के लिये त्रिदलीय वेतन बोर्ड स्थापित किये गये हैं। दूसरे बड़े उद्योगों के लिये भी यथामय ऐसी बोर्ड स्थापित करने का मेरी सरकार का विचार है। फिलहाल कुछ चूने हुए उद्योग-धन्धों में ऐसी योजनाएं चालू की गयी हैं। जिन से उद्योगों के संचालन में मजदूर अधिकाधिक भाग ले सकें। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया जा रहा है और १९५२ के कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम को अब १९ उद्योगों पर लागू कर दिया गया है और इस अधिनियम के अन्तर्गत अब ६२१५ कारखाने आ गये हैं। चन्दे की कुल रकम प्रायः १०० करोड़ रुपये जमा हो चुकी है।

नागा पहाड़ी इलाके की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अगस्त १९५७ में कोहिमा में आयोजित नागा लोगों के सम्मेलन के नेताओं ने जो मांगें पेश की थीं उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इस के फलस्वरूप नागा पहाड़ी क्षेत्र और त्यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन को मिलाकर गत नवम्बर में संसद् के अधिनियम के द्वारा एक नई इकाई बना दी गई है।

१९५७ में संसद् ने ६८ विधेयकों को पारित किया और इस समय ८ विधेयक आपके विचाराधीन हैं। चालू सत्र में वाणिज्य, जहाजों बेड़ा (मर्चेण्ट शिपिंग) व्यापार बिन्हु (ट्रेड मार्क) और वाणिज्य बिन्हो (मर्चेण्टाइज मार्क) के सम्बन्ध में विधान प्रस्तुत करने का मेरी सरकार का विचार है। विभिन्न मामलों से सम्बन्धित संशोधन विधान भी आपके समक्ष रखे जायेंगे।

आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आकड़ों का विवरण आपके समक्ष रखा जायेगा।

विदेशों से हमारे सम्बन्ध बराबर मंत्रीपूर्ण बने रहें। पिछली बार जब मैंने संसद् के समक्ष अभिभाषण दिया था उस समय से अबतक गणराज्य के सम्मानित अतिथियों के रूप में इण्डोनेशिया, वियेतनाम गणराज्य और वियेतनाम प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य के राष्ट्रपतियों का, युगोस्लाव संघ प्रशासनिक परिषद् के उपराष्ट्रपति का, बर्मा, श्रीलंका चेकोस्लोवाकिया, जापान और इंग्लैंड के प्रधानमंत्रियों का, फ्रांस और मोरक्को के विदेश मंत्रियों का, घाना के वित्तमंत्री का, घाना और मौरिशस के शिक्षा मंत्रियों का और कई देशों में आने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करने का हमें श्रेय मिला।

गत जून के अन्त में मेरे प्रधान मंत्री ने लन्दन में होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने सीरिया, डेन्मार्क, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, मिन्न, सूडान, जापान, बर्मा और श्रीलंका की भी यात्रा की। उपराष्ट्रपति ने भी चीन मंगोलिया, वियेतनाम, कम्बोडिया, लाओस और श्रीलंका की सद्भावना यात्रा की।

यद्यपि कोई तात्कालिक संकट विद्यमान नहीं, फिर भी ससार की स्थिति संकटपूर्ण है। यह आशांका बराबर बनी है कि यदि

[राष्ट्रपति]

गतिरोध, और तनाव की भावना को रोका नहीं गया और विशेषकर बड़े राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व की नींव नहीं रखी गई, तो किसी भी समय स्थिति बिगड़ कर विश्व-व्यापी सघर्ष का रूप ले सकती है।

सोवियत संघ और मयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उपग्रहों का सफल प्रयोग मानव का देश और काल की विजय की दिशा में एक त्रातिकारी कदम है। यह विज्ञान की महान उन्नति का प्रतीक है किन्तु विश्व की तनावपूर्ण स्थिति को और अन्तर्-महाद्वीपीय प्रक्षेपण अस्त्रों को देखते हुये यह मानना पडेगा कि वैज्ञानिक आविष्कार विश्वशान्ति के लिये एक नया संकट पैदा कर सकते हैं।

निष्शस्त्रीकरण की दिशा में राष्ट्रों के प्रयत्नों में गतिरोध पैदा हों गाया है। इस समस्या के सफलतापूर्ण हल के लिये यह आवश्यक है कि अमेरिका और मावियत संघ द्वारा सम्मिलित प्रयत्न किया जाए और जो भी निर्णय लिया जाए, उन में ये दोनों राष्ट्र सहमत हों। मयुक्त राष्ट्रों की पिछली साधारण सभा में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई थी, किन्तु गतिरोध बराबर बना है। फिर भी साधारण सभा ने सर्वसम्मति में शान्तिपूर्ण सहग्रस्तित्व के पक्ष में एक प्रस्ताव पाम किया। यह प्रस्ताव निष्शस्त्रीकरण के प्रश्न पर गतिरोध के बाद पाम किया गया, इस लिये यह आशा हानी है कि इस मामले पर नवीन दृष्टिकोण में फिर विचार किया जाएगा।

मेरी सरकार का यह मन है कि बड़े राष्ट्रों की ऊंचे स्तर पर बातचीत जिस में वे ऐसे राष्ट्रों को भी साथ ले सकें जिनके बारे में वे सहमत हों, तनाव का दूर करने में, मयुक्त राष्ट्र के १६ दिसम्बर, १९५५ के प्रस्ताव के अनुसार शान्तिपूर्ण महिष्णुता का वातावरण पैदा करने में और निष्शस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने में, सहायक होगी।

संयुक्त राष्ट्र में मेरी सरकार बराबर तनाव दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न करती रही है। मेरी सरकार का यह मत है कि सह-अस्तित्व और एक दूसरे के प्रति आदर की भावना द्वारा ही इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।

भारत को निष्शस्त्रीकरण : आयोग का सदस्य निर्वाचित किया गया है। यह आयोग सफलतापूर्वक सभी कार्य कर सकता है जब ममस्त सम्बन्धित देश इस में भाग लेने को तयार हों। मेरी सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करेगी।

मयुक्त राष्ट्र में और उसके बाहर भी मेरी सरकार गणविक विस्फाट पर राक लगाने के लिये बराबर जार देती आ रही है। इन विस्फाटा क मकड स विज्ञानवेत्ता और ममार के जनसाधारण अधिवाधिक चिन्तित हाने जा रहे हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने मयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा मावियत संघ के सर्वोच्च अधिवास्त्रियों में निष्शस्त्रीकरण की आर प्रथम पग के रूप में इन विस्फाटा का स्थगित करने की यपोल की है। इस दिशा में मेरी सरकार अपनी काशिश जारी रखेगी।

इंडोनाइजा में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग, जिनका भारत अध्यक्ष है, कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और वहा शान्ति स्थिर रखी जा सकी है। लाओस में लाओस की सरकार और पायंट लाओस के नेताओं के बीच समझौता एक शुभ घटना है और अब उस देश में राजनैतिक समझौते का मार्ग प्रशस्त समझना चाहिये।

मेरी सरकार ने यह खबर आश्चर्य और दुःख के साथ सुनी कि बगदाद संधि के हाल में होने वाले अधिवेशन में कुछ देशों ने आणविक शस्त्रों से सज्जित हाने की माग की। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि कोई भी

बड़ा राष्ट्र इस प्रकार के दृष्टिकोण और ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहन नहीं देगा ।

अपने बारे में मेरी सरकार इस बात को असंदिग्ध रूप में स्पष्ट कर देना चाहती है कि यद्यपि हमें आज वैज्ञानिक ज्ञान और साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा यदि हम अपनी नासमझी में चाहें तो आणविक शस्त्र तैयार कर सकते हैं, तो भी हमारी कदापि यह इच्छा नहीं कि हम ऐसे शस्त्रों को प्राप्त करें अथवा तैयार करें अथवा उन का कभी प्रयोग करें या किसी अन्य देश द्वारा उन के प्रयोग को क्षमणीय समझें । इस क्षेत्र में हमारे प्रयत्न शान्तिपूर्ण उपयोग के लिये अणुशक्ति के उत्पादन तक ही सीमित रहेंगे ।

संसद् के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूँ और मेरा विश्वास है कि आपके प्रयत्न हमारे लोगों को अधिक सम्पन्न और सन्तुष्ट बनाने में और विश्व में शान्ति तथा सहयोग का मंचार करने में सहायक होंगे ।

The President: Members of Parliament, I am happy to welcome you once again to your labours in a new session of Parliament.

We are about to complete the second year of our Second Five Year Plan. Our economy, as you are well aware, has been under considerable stress since the beginning of the Second Plan period. In my address to you last May, I said that—

“It would be the easier, but not the gainful or constructive way, to bridge the gaps to which I have referred, by halting development. This will, however, provide no real or long-term remedy. Our endeavour has to be to mobilise and conserve resources for greater productivity and for maintaining and improving development. My Government are fully aware of the problem and of the effort required. They are equally concerned that our temporary difficulties should not lead us in the direction

of retarding progress and development, but that the difficulties should be overcome, where necessary, by reconsideration and revision of methods and by planned mobilisation of resources, and not by either the abandonment or slowing down of the progress towards our objectives.”

My Government have taken, in many spheres of our economic and social life, steps that are very stringent to enable our economy and our planned development to absorb the shock of these stresses, thereby controlling to a great extent inflationary factors and meeting the situations resulting from the position in regard to foreign exchange resources and for the completion of the tasks under the Plan. The measures my Government have taken in this regard have yielded results and in recent months, I am happy to say, there has been some improvement. The measures adopted by my Government to restrict imports and to earn more foreign exchange have resulted recently in some diminution in the rate at which our foreign assets were falling. My Government have also endeavoured and succeeded in some measure in obtaining foreign assets by way of loans, arrangements in regard to specific projects, deferred payments for essential capital goods and severe limitation of allocation of foreign exchange to all but the most essential capital or consumption requirements. I should like to express my gratitude to the countries from whom we have received assistance in this respect. In this connection I would like to mention the Soviet Union, Canada, Germany, Japan and, more particularly, the United States of America.

Increased production, which would both help to reduce foreign exchange requirements and also help to earn it, and domestic savings, which help to check inflation and provide the internal resources required for the fulfilment of our plan tasks, are, however, imperative. These call for both un-

[President]

derstanding of problems and sacrifices from our people, for vigilance, economies and the support of public opinion.

The series of measures taken by my Government in regard to fiscal and foreign exchange matters have assisted in maintaining the stability of our economy. Prices which had been rising in 1956 and the early part of 1957, have not only remained steady, but registered a slight fall towards the end of last year, which is continuing. There has also been an appreciable decline in our Balance of Payments deficit. The credit position is considerably easier than it was last year. The resources of the banking system have improved and the increase in their advances has been moderate. The Reserve Bank proposes to watch the situation carefully with a view to keeping down any speculative tendencies.

The availability and price of foodgrains very largely govern our internal price levels and our external payment position. The damage to crops as a result of drought in certain parts of the country has been a very disquieting feature. My Government have at their disposal reserves of food which would be maintained at adequate levels by further imports; and have also imposed a degree of limited but essential controls on the movement of foodgrains. My Government have also regulated the supply of bank credit for foodgrains to prevent hoarding and arranged for distribution of large quantities of foodgrains from Government stocks through Fair Price Shops. These measures have appreciably helped to restrain the upward trend in prices.

In 1956-57, even though the harvest was not good, the production of foodgrains almost touched the peak level reached in 1953-54. It was 68.7 million tons which was more than 5 per cent. higher than the figure for 1955-56. The all India index of agricultural production showed an increase of about 6 per cent. over the previous year. The production of commercial crops also

recorded a significant increase. This was 18 per cent in regard to cotton, 13 per cent. for sugarcane and 6 per cent. for oil seeds. All possible efforts are being made to increase food production at a higher rate than hitherto. It is essential that self-sufficiency in food should be attained.

Industrial production has maintained steady improvement. One wholesome result of the severe restrictions in imports, necessitated by the paucity of foreign exchange, is greater employment of domestic resources and skills and their development. Progress in this direction, which it is the aim of my Government to encourage and promote, both in regard to Governmental requirements and industry generally, is essential, if productivity and the growth of our economy are not to be retarded. The success of these developments, although brought about by necessity, would have the effect of making our industry less dependent on outside sources.

The production of coal during 1957 reached a new limit of 43 million tons as against 39 million tons in 1956. Drilling and prospecting have been almost completed in many important new areas and it is expected that several new collieries will be working within a few months.

An agreement has recently been concluded with the Assam Oil Company for the formation of a Rupee Company in which Government will participate to the extent of 33½ per cent. for the production of oil from the Naharkatiya oil fields and for transportation of oil therefrom. Two refineries, one in Assam and the other in Bihar, are also to be set up. Prospecting and drilling for oil are taking place in other parts of the country also.

A non-lapsable Shipping Development Fund, with a view to finding an assured source of rupee finance for the rapid growth of Indian shipping has been established.

The multi-purpose river valley projects have made considerable progress.

Matihon Dam in the Damodar Valley was inaugurated in September last. In the Bhakra project work is proceeding ahead of schedule. In Nagarjunasagar construction of the dam began in July last. Progress in regard to the other multi-purpose projects has also been generally satisfactory.

In the field of heavy industry, much progress has been made. In the public sector, a heavy machine building plant and a number of other projects will be financed out of special credit offered by the Government of the U.S.S.R. A heavy foundry and forge will be set up with Czechoslovak collaboration. A fertiliser factory at Nangal is being built with the help of credit terms from the United Kingdom, France and Italy. It is proposed to build another fertiliser plant at Neyveli. The heavy electrical plant at Bhopal is being taken in hand with British collaboration. Good progress has been made in the construction of the three major steel plants at Rourkela, Bhilai and Durgapur.

The Malaria Control Programme, which was inaugurated in 1953, has made considerable progress and reduced greatly in incidence of malaria. From control, our efforts are now being directed to a complete eradication of malaria. In regard to filaria control also, good progress has been made. Provision has been made for slum clearance and development programmes.

Marked progress continues to be made in the field of science and technology, and our National Laboratories are directing their efforts to the solution of scientific problems related to industrial and national development plans. In particular, efforts are being made for the rapid increase of technical manpower.

The work of the Department of Atomic Energy has expanded greatly during the last year. Two more reactors and several new plants are under construction. Uranium metal of atomic purity and fuel element for the reactors will be in production before the

end of the current year. My Government have under consideration the construction of one or more Atomic Power Stations during the current Five Year Plan period.

The State Bank of India, which was nationalised a little more than two and a half years ago, has made considerable progress. Measures are under consideration to integrate more closely with the State Bank of India certain other State associated banks of intermediate size, which will be managed as subsidiaries of the State Bank.

The Planning Commission is engaged in working out the annual plans for the States and the Centre and the necessary adjustments in the Plan as a whole, having regard to the available resources and, at the same time, to the imperative consideration of not permitting any impairment to the growth of our economy. My Government will place before you in the current session the results of these studies in regard to what is spoken of at the "Core of the Plan".

The Community Development and National Extension Service Projects have made significant progress. There are now 2,152 Blocks which comprise 2,76,000 villages and cover 15 crores of population. The National Development Council having decided that the Block should be the unit for planning and development and the common agency of all development departments, steps have been taken to integrate Departmental Development Budgets in the Block Budget. The Block Development Officer is being placed in operational control of this budget. The Development Council have also decided on greater decentralisation in regard to administration and the transfer of greater authority to people's organisations at the village block and district levels. The pattern of such devolution will be worked out by the States according to local circumstances. A scheme for training

[President]

village farm leaders has been initiated to encourage the adoption of improved agricultural methods

The recommendations of the Official Language Commission which are being studied by a Committee of 30 Members of Parliament are under examination. Members of Parliament, you will have an early opportunity of discussing this Report and the opinions of your Committee before any directives are issued.

Requisite action in pursuance of the Delhi Municipal Corporation Act of 1957 to establish a Corporation in the beginning of the next financial year has been taken.

Tripartite Wage Boards have been set up in the textile and sugar industries. My Government have under consideration the setting up of similar wage boards for other major industries in due course. With a view to securing the progressive participation of workers in industrial management, schemes to this end are being introduced initially in a few selected undertakings. The Employees' State Insurance Scheme is being extended and the Employees' Provident Fund Act of 1952 has been extended now to cover 19 industries, 6,215 factories and establishments are now covered under the Act. The total amount of contributions collected are about 100 crores of rupees.

The situation in the Naga Hills area has improved considerably. Government accepted the demands of the leaders of the Naga People's Convention held at Kohima in August 1957 and, as a result, a new unit comprising the Naga Hills and the Tuensang Frontier Division was created by Act of Parliament in November last.

Sixty-eight Bills were passed by Parliament during 1957 and eight Bills are pending before you. My Government propose to introduce legislation in the current session in regard to Merchant Shipping and Trade Mark and Merchandise Marks. Certain other amending legislation in regard to various matters will also be submitted to you.

A statement of the estimated receipts and the expenditure of the Government of India for the ensuing financial year will be laid before you.

Our relations with foreign countries continued to be friendly. Since I addressed Parliament last, we have had the privilege of receiving as guests of the Republic, the Presidents of Indonesia, the Republic of Vietnam, and the Democratic Republic of Vietnam, the Vice President of the Yugoslav Federal Executive Council, the Prime Ministers of Burma, Ceylon, Czechoslovakia, Japan and the United Kingdom, the Foreign Ministers of France and Morocco, the Finance Minister of Ghana, the Education Ministers of Ghana and Mauritius, and cultural delegations from several countries.

My Prime Minister attended the meeting of the Commonwealth Prime Ministers in London at the end of June. He also visited Syria, Denmark, Finland, Norway, Sweden, Egypt, Sudan, Japan, Burma and Ceylon. The Vice-President was also able to pay goodwill visits to China, Mongolia, Vietnam, Cambodia, Laos and Ceylon.

The world situation, while at present no aspects of an immediate crisis is ominous with the ever present danger of deterioration into conflict which might become world wide, unless the present deadlocks and world tensions are eased and the way is found for peaceful co-existence of nations, more particularly between the Great Powers.

The launching of the earth satellites by the Soviet Union and the United States of America marks an epochal advance by Man in the conquest of Time and Space. They are great scientific advances but in the context of world tensions and the presence of inter-continental ballistic missiles and other weapons, every such scientific advance can well become another threat to world peace.

The efforts towards achieving progress in disarmament stand deadlocked. Any effective solution requires

the joint participation of the two Great Powers—the United States of America and the Soviet Union—and their agreement in regard to any solution. At the last General Assembly of the United Nations, some progress was made in this direction, but the deadlock continues. That General Assembly, however, passed a unanimous resolution on peaceful co-existence which, following as it did the deadlock over disarmament, gives some hope that a fresh approach may still be made.

My Government holds the opinion that a meeting at high level of the great States with any others, on whom they might agree, would help to ease tensions, would bring about an atmosphere of peaceful tolerance, as provided in the United Nations Resolution of December 14, 1957, and open the way towards the easing of tensions and some progress in the field of disarmament.

My Government have engaged themselves at the United Nations in continued efforts to help to ease tensions and to advance the view that on co-existence and respect of each other alone can solutions be found.

India has been elected as a member of the Disarmament Commission. The Commission can, however, meet effectively only if all countries concerned are willing to participate. My Government intend to do their utmost to help to bring about a solution.

My Government continue to press in the United Nations and elsewhere for the suspension of nuclear explosions, the dangers of which are becoming more and more the concern of scientists and indeed of peoples all over the world. My Prime Minister made an appeal to the heads of the United States of America and the Soviet Union in regard to suspension of these tests as a first step towards disarmament. My Government will continue their efforts in these fields.

The International Supervisory Commissions in Indo-China, of which India is Chairman, have continued to function effectively despite difficulties and peace in that area has been

maintained. A welcome development has been an agreement reached in Laos between the Royal Laotian Government and the Pathet Lao leaders and a political settlement there is within sight.

My Government have heard with regret and surprise reports that some countries had sought at a recent meeting of the Baghdad Pact to be equipped with atomic weapons. We profoundly believe that none of the Great Powers will give encouragement to these desires and the outlook that persists.

For ourselves, my Government desire to make it clear beyond all doubt, that while we could, if we so decided, unwisely, produce atomic weapons, with the resources and skills that we have and can develop, we have no intention whatsoever of acquiring, manufacturing or using such weapons or condoning their use by any State. Our endeavours in the atomic field will remain confined to the peaceful use of atomic energy.

Members of Parliament, I wish you success in your labours, and trust that they may help to bring greater prosperity and contentment to our people and peace and co-operation in the world.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table the following seven Bills passed by the Houses of Parliament during the last Session and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th December, 1957:

1. The Central Excises and Salt (Amendment) Bill, 1957.
2. The Union Duties of Excise (Distribution) Bill, 1957.
3. The Appropriation (No. 5) Bill, 1957.
4. The Estate Duty and Tax on Railway Passenger Fares (Distribution) Bill, 1957.